विकेंद्रीकरण से मुमकिन है तीव्र विकास

कार्यशाला

नियोजन और मानव विकास पर हुई दो दिवसीय वर्कशॉप में गुरुवार को व्यवस्था में विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया कि इससे बेहतर गवर्निंग के साथ ही पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाया जा सकता है।

सिटी रिपोर्टर. रायपुर

केन्द्र की बात करें या राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की कोई अपना हक दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहता। जबकि, विकेंद्रीकरण योजना के तहत राज्य ही नहीं जिला स्तरीय और पंचायत स्तर पर भी योजनाओं के क्रियान्वयन का अधिकार होना चाहिए।

जेल रोड स्थित एक होटल में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और योजना आयोग की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई। विकेंद्रीकरण की नीति पर सटीक ढंग से काम करने के मकसद से कार्यशाला रखी गई। इंक्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की इस कार्यशाला में अंतिम दिन पंचायत स्तर के जन प्रतिनिधियों ने ग्राम स्तर पर किए जा रहे कार्य प्रजेंट किए। कोरबा के फारुख सिद्दकी ने विकेंद्रीकरण योजना के साथ कन्वर्जेंस मॉडल की जानकारी दी।

इसके तहत कोरबा के ऐसे लोग जिनकी आय का एक मात्र जरिया कृषि था, उन्हें कृषि की उन्नत करने हेतु आधुनिक तौर तरीकों से परिचय करवाया गया। उनकी जरूरतें जैसे स्वरोजगार, अच्छा जीवन स्तर और फूड सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर भी ग्राम स्तर पर इस मॉडल के तहत काम किया गया। फारुख ने बताया कि यह आसान नहीं था, इसलिए हमने एक गांव को बतौर मॉडल पेश किया और लोगों को इसे देखने को कहा। इस तरह सुविधाएं जन जन तक पहुंचती गईं।

आज इस मॉडल के तहत देश के 2131 ग्रामों का विकास संभव हो सका है। ऐसे ही कई जनप्रतिनिधियों ने प्रजेंटेशन दिए। कार्यक्रम का सेकंड सेशन फीडबैक का रहा।

वैसा ही हो लोकतंत्र: समापन अवसर के पहले सेशन में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद गौतम बंदोपाध्याय ने कहा कि विकेंद्रीकरण विकास के लिए हमें विकेंद्रीकरण लोकतंत्र की आवश्यकता है, जो थोड़ा मुश्किल है। जब विकास हमारे लिए हो रहा है, तो यह भी हमें ही तय करना होगा कि विकास कैसा हो। ऐसा कोई कानून नहीं जो आदिवासियों के हितों की रक्षा कर सकें। यूएनडीपी की योजना के तहत शहर में आयोजित कार्यशाला इस कार्यक्रम का अंतिम चरण था। 2013 के लिए यूएनडीपी (यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्लान) संभवतः एक नई योजना के साथ विकेंद्रीकरण पर काम करे। चूंकि यह गसला विकासशील देशों में बड़ा अहम है। इस अवसर पर आईएम फोर चेंज के डायरेक्टर विपुल मुदगल, सत्येंद्र रंजन समेत राज्य के अनेक मीडियाकर्मी मौजूद रहे।

एक संस्था की ओर से नियोजन और मानव विकास विषय पर हुई दो दिनी चर्चा के अंतिम दिन विकेंद्रीकरण पर बात की गई।

डिसेंट्रलाइजेशन इन सिस्टम

किसी भी राजनैतिक, संवैधानिक अथवा शक्ति संपन्न व्यवस्थाओं को विकेंद्रित करके अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। व्यवस्थाओं के अनेक चिंतक भी ऐसा मानते हैं कि विकेंद्रीकरण लोक सशक्तिकरण का हिस्सा है। इससे दो फायदे होते हैं, पहला तो व्यवस्था किसी भी तरह की तानाशाही या शक्ति के केंद्रीकरण से बची रहती है, दूसरा व्यवस्था में देश की लोक भागीदारी अधिक से अधिक हो पाती है। यह दोनों ही बातें विकेंद्रीकरण की सबसे बड़ी खूबियां हैं।